

मेसर्स द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण

बनाम

उत्तर प्रदेश का राज्य और अन्य

[मेहर चंद महाजन सी. जे., मुखर्जी, विवियन बोस, गुलाम हसन और
जगन्नाथ जे.]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 (1) (छ), 19 (6)-उत्तर प्रदेश
कोयला नियंत्रण आदेश, 1953 का खंड 4 (3), क्या यह संविधान से
बाहर है।

एक कानून या व्यवस्था जो सामान्य रूप से उपलब्ध वस्तुओं में
व्यापार या व्यवसाय को विनियमित करने के मामले में कार्यपालिका को
मनमाना और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करती है, उसे अनुचित माना जाना
चाहिए। उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1953 के खंड 4 (3) के
तहत, लाइसेंस प्राधिकरण को इस आदेश के तहत किसी भी लाइसेंस को
देने या देने से इनकार करने, नवीनीकरण करने या नवीनीकरण करने,
निलंबित करने, रद्द करने या संशोधित करने से इनकार करने की पूर्ण
शक्ति दी गई है और उसे केवल अपनी कार्रवाई के कारणों को दर्ज करना
है। इतना ही नहीं, शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा
सकता है जिसे राज्य कोयला नियंत्रक इसे सौंपने का विकल्प चुन सकता

है, और चुनाव किसी भी और प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधानों को उचित नहीं माना जा सकता है:

इसलिए यह माना गया कि सी. एल. का प्रावधान। उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1953 के 4 (3) को अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के रूप में अमान्य माना जाना चाहिए। संविधान का 19 (1) (छ) और अनुच्छेद के खंड (6) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के दायरे में नहीं आता है।

यूक वो बनाम हॉपकिंस (373 पर 118 यू. एस. 356) का उल्लेख किया गया।

मूल क्षेत्राधिकार: 1953 की याचिका सं. 326

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल याचिका।

याचिकाकर्ताओं के लिए एस. सी. इसाक्स (उनके साथ एस. के. कपूर)।

उत्तरदाताओं के लिए एच. जे. उमरीगर।

11 जनवरी 1954

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मुखर्जिया जे.

यह याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) के खंड (च) और (छ) के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की गई है और अनिवार्य प्रकृति के रिट जारी करके इसे लागू करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए, भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक होगा। याचिकाकर्ता व्यापारियों की एक फर्म है, जो अपने लाइसेंस को रद्द करने से पहले कानपुर शहर में अपने द्वारा आयोजित एक कोयला डिपो में कोयले के खुदरा विक्रेताओं का व्यवसाय कर रहे थे। यह कहा जाता है कि कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ जिला आपूर्ति अधिकारी, जो याचिका में क्रमशः 2 और 3 प्रतिवादियों के रूप में शामिल हैं, काफी समय से याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ शहर के अन्य कोयला डिपो धारकों को समय-समय पर निर्देश जारी कर रहे थे, जिसमें कोयले, सॉफ्ट कोक आदि की बिक्री पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। यह कहा गया है कि 14 फरवरी, 1953 से पहले जिला अधिकारियों द्वारा तय की गई कीमतों के कारण कोयला विक्रेताओं को सॉफ्ट कोक की बिक्री पर 20 प्रतिशत और हार्ड कोक और स्टीम कोयले की बिक्री पर 15 प्रतिशत लाभ हुआ था।

भूमि की लागत में कई वस्तुएँ शामिल थीं और पूर्व-कोयला मूल्य, बिचौलिये के कमीशन और रेलवे माल ढुलाई के अलावा, श्रम शुल्क, लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क, कार्टेज और स्टैकिंग खर्च सहित विभिन्न प्रकार के आकस्मिक खर्च थे। इन लागत तत्वों में से कुल बनाने के बाद, वजन की कमी के लिए 5 एम. डी. एस. की दर से भत्ता दिया गया था। और सॉफ्ट कोक और 3 एम. डी. एस. के मामले में विषम सीर प्रति टन. और कठोर कोक और भाप कोयले के मामले में विषम सीर, और यह शुद्ध वजन के आधार पर था कि कीमत की गणना की गई थी। 14 फरवरी, 1953 को जिला आपूर्ति अधिकारी ने कोक, कोयला आदि की बिक्री कीमतों को मौजूदा दरों से बहुत कम करने का निर्देश जारी किया। यह कमी तीन गुना तरीके से की गई। सबसे पहले, वजन की कमी के लिए भत्ता पहले की तुलना में बहुत कम किया गया था; दूसरा, रु. 4-12-0 को केवल सभी आकस्मिक खर्चों के लिए अनुमति दी गई थी, और तीसरा, लाभ के मार्जिन को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। 22 मई, 1953 को कानपुर के सात कोयला खदान डिपो धारकों द्वारा एक प्रतिनिधि याचिका दायर की गई थी, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने 14 फरवरी, 1953 के कार्यकारी आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस याचिका के संबंध में अंतरिम ठहराव के लिए

एक आवेदन था जो 1 जुलाई, 1953 को इस अदालत के विद्वान अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। उस दिन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस आशय का वचन दिया गया था कि वे 14 फरवरी, 1953 के आदेश को वापस ले लेंगे और जाहिर तौर पर यह वचन देने में राज्य के साथ विचार यह था कि यह विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी आदेश था जिसके पीछे कोई विधायी मंजूरी नहीं थी। 14 फरवरी के आदेश को वास्तव में वापस ले लिया गया था, लेकिन 10 जुलाई, 1953 को उत्तर प्रदेश राज्य ने एक अधिसूचना द्वारा "उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1953" नामक एक आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना था, जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी भारत सरकार के अधिसूचित आदेश के साथ पढ़ा गया था। चूंकि इस कोयला नियंत्रण आदेश की संवैधानिकता वर्तमान कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं द्वारा हमले का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए आदेश के भौतिक प्रावधानों को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा, जिसके संबंध में पक्षों के बीच विवाद मुख्य रूप से केंद्रित है।

"उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1953

2. इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो

(क) "कोयले" में कोक शामिल है लेकिन इसमें सिंडर और राख शामिल नहीं है. (ग) "लाइसेंस प्राधिकरण" का अर्थ है जिले का जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस आदेश के तहत अपने कार्य करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी और इसमें जिले का जिला आपूर्ति अधिकारी शामिल है.

(घ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है फॉर्म 'ए' या फॉर्म 'बी' में इस आदेश के प्रावधानों के तहत लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति।

3. (1) कोई भी व्यक्ति इस राज्य में ईंटों को जलाने के लिए कोयले का भंडारण, बिक्री, भंडारण या उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा कोयले का निपटान नहीं करेगा, सिवाय इस आदेश के तहत दिए गए फॉर्म 'ए' या 'बी' में लाइसेंस के तहत या इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार।

(2) उपखंड (1) में निहित कुछ भी नहीं-(क) जहां तक यह अपने उपभोग के लिए कोयले के भंडारण या भंडारण के लिए लाइसेंस लेने से संबंधित है, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य कोयला नियंत्रक की अनुमति पर अपने उपयोग के लिए कोयला प्राप्त करने वाले व्यक्तियों या उपक्रमों द्वारा रखे गए स्टॉक पर लागू होगा।

4. (1) इस आदेश के तहत लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन इस आदेश में संलग्न अनुसूची 1 में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

(2) इस आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस इस आदेश के साथ संलग्न फॉर्म 'ए' या फॉर्म 'बी' में होगा और इस आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस धारक कोयले की खरीद, बिक्री, भंडारण या वितरण के संबंध में लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा उसे जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है, देने से इनकार कर सकता है, नवीनीकरण कर सकता है या नवीनीकरण से इनकार कर सकता है और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी अनुज्ञप्ति या किसी भी शर्त को निलंबित, रद्द, रद्द या संशोधित कर सकता है। बशर्ते कि इस आदेश के तहत अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक शक्ति का उपयोग राज्य कोयला नियंत्रक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भी किया जाएगा।

7. राज्य कोयला नियंत्रक इसी प्रकार लिखित आदेश द्वारा कोयले का भंडार रखने वाले किसी भी व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी शर्तों और कीमतों पर स्टॉक का पूरा या कोई हिस्सा बेचने की अपेक्षा कर सकता है जो खंड (8) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाएं।

8. (1) प्रपत्र 'ख' में कोई भी अनुज्ञप्तिधारी और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूची III में दिए गए सूत्र के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत से अधिक कीमत पर कोयले को नहीं बेचेगा, बेचने के लिए सहमत नहीं होगा या बेचने की पेशकश नहीं करेगा।

(2) प्रपत्र 'क' में अनुज्ञप्तिधारी या कोयले का भंडार रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के लिए या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या खंड 6 या खंड 7 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे भंडार का हस्तांतरण या निपटान करने वाला व्यक्ति कोयले के लिए भूमि लागत से अधिक कीमत, साथ ही आकस्मिक और संचालन शुल्क, और भूमि लागत के 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं लेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या राज्य कोयला नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाए।

व्याख्याएँ: - (1) भूमि पर उतरने की लागत का अर्थ है कोयले की पूर्व कोयला खदान कीमत के साथ <आई. डी. 1. और बिहार बिक्री कर के साथ वास्तव में भुगतान किए गए बिचौलिये का कमीशन और रेलवे माल ढुलाई।

(2) आकस्मिक और हैंडलिंग शुल्क का अर्थ है वैगनों से उतारने की लागत, स्टैकिंग साइट पर परिवहन, स्टैकिंग साइट पर उतारने की

लागत, साथ ही गोदाम का किराया, और चौकीदारी शुल्क, यदि कोई हो, तो रुपये से अधिक नहीं। 8-8-0 प्रति टन जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या राज्य कोयला नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

11. जिला मजिस्ट्रेट इस आदेश के प्रारंभ होने के एक सप्ताह के भीतर अपने जिले में कोयले की बिक्री का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की एक सूची स्थानीय पत्र में तैयार और प्रकाशित करेगा और सूची के प्रकाशन के बाद, इसमें शामिल व्यक्तियों को इस आदेश के उद्देश्यों के लिए फॉर्म ए या बी में सूची के प्रकाशन के बाद अगले तीन महीने तक लाइसेंसधारी माना जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

12. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी भी प्रावधान या उसके तहत दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत दंडनीय होगा, जिसमें तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ और किसी अन्य सजा के प्रतिकूल प्रभाव के बिना दंडनीय होगा, जिसके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है।

आदेश में निर्दिष्ट अनुसूची III इस प्रकार है:

अनुसूची III

(सॉफ्ट कोक/हार्ड की कीमतों की घोषणा के लिए सूत्र कोक/भाप कोयला)

1. पूर्व-कोयला खान मूल्य - वास्तविक
2. L.D.C.C. और बिहार बिक्री कर- वास्तविक
3. बिचौलिया का कमीशन - वास्तव में भारत सरकार के कोयला नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 6 के तहत अधिकतम सहायता के अधीन भुगतान किया जाता है।
4. रेलवे माल ढुलाई - वास्तविक
5. आनुषंगिक और हैंडलिंग खर्च जिसमें शामिल है - अधिकतम रु. 8-80 प्रति टन जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि उन स्थानों पर जो रेलवे शीर्ष से असाधारण रूप से दूर हैं, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा उच्च दर की अनुमति दी जा सकती है।
 - (i) वैगनों से उतारना
 - (ii) ढेर के परिसर तक परिवहन
 - (iii) परिसर या डिपो पर उतराना और ढेर करना
 - (iv) गोदाम का किराया और चौकीदारी शुल्क, यदि कोई हो
 - (v) भार के खर्च यदि कोई हो।
6. स्थानीय कर आक्ट्राय आदि वास्तविक

7. कमी - सॉफ्ट कोक के मामले में 3.5 टन प्रति टन और हार्ड कोक और भाप कोयले के मामले में 2.5 टन प्रति टन से अधिक नहीं, जैसा कि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

8. फायदा - मद संख्या 5 को छोड़कर उपरोक्त 1 से 6 तक की कुल मद पर 10 प्रतिशत

ऐसा कहा जाता है कि 16 जुलाई, 1953 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक घोषणा जारी की जिसमें उन्होंने सॉफ्ट कोक, कोयला आदि की बिक्री के लिए खुदरा दरें ठीक उन्हीं आंकड़ों पर निर्धारित कीं जो वे 14 फरवरी, 1953 को जारी किए गए निर्देश में थीं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसका परिणाम यह हुआ कि बिक्री मूल्य इतने कम हो गए कि कोयला व्यापारियों के लिए अपना व्यवसाय जारी रखना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ऊपर निर्धारित नियंत्रण आदेश के खंड 11 के प्रावधान के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का नाम बी लाइसेंस धारकों की सूची में दिखाई दिया और उन्होंने खंड (4) द्वारा आवश्यक उचित रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन किया। कहा जाता है कि लाइसेंस तैयार किया गया था, हालांकि वास्तव में याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया था। 3 अक्टूबर, 1953 के एक पत्र द्वारा, क्षेत्र राशन अधिकारी, कानपुर ने याचिकाकर्ताओं पर कोयला डिपो के संचालन के संबंध में कई अनियमितताएं करने का आरोप लगाया। आरोप मुख्य रूप से यह था कि दो अन्य डिपो थे जो याचिकाकर्ताओं द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर आयोजित और

वित्तपोषित किए गए थे और याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित दरों से अधिक पर कोयले की बिक्री के लिए समझौते किए थे। याचिकाकर्ताओं ने एक स्पर्धीकरण प्रस्तुत किया जिसे संतोषजनक नहीं माना गया और 3 अक्टूबर, 1953 को एक आदेश जारी किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी, कानपुर ने याचिकाकर्ताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 10 जुलाई, 1953 के कोयला नियंत्रण आदेश की वैधता, 16 जुलाई को की गई कीमतों की घोषणा और 13 अक्टूबर, 1953 को याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को भी चुनौती दी है।

उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश की संवैधानिक वैधता पर हमारे समक्ष इस आधार पर काफी हद तक हमला किया गया है कि इसके प्रावधान लाइसेंस देने या रद्द करने, कोयले की कीमतें तय करने और व्यापारियों पर शर्तें लगाने के मामले में लाइसेंस प्राधिकरण या राज्य कोयला नियंत्रक में एक निरंकुश और निर्देशित विवेकाधिकार निहित करते हैं। और इन मनमानी शक्तियों का प्रयोग केवल अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें उनकी पसंद के किसी भी व्यक्ति को सौंप दिया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने व्यापार और व्यावसायिक संघर्ष को जारी रखने के

याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं और इसलिए अमान्य हैं। 16 जुलाई, 1953 के उस आदेश के संबंध में, जिसके द्वारा कोक, कोयले आदि की कीमतें निर्धारित की गई थीं, यह बताया गया है कि यह न केवल कोयला नियंत्रण आदेश द्वारा लाइसेंस प्राधिकरण को प्रदान की गई मनमानी शक्ति का उपयोग करते हुए बनाया गया था, बल्कि निर्धारित कीमतें स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अन्य स्थानों जैसे इलाहाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ में उसी नियंत्रण आदेश के तहत निर्धारित कीमतों के साथ उनकी तुलना करने से प्रतीत होती हैं। याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को रद्द करने वाले 13 अक्टूबर, 1953 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और अनिश्चित थे और यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कोयला व्यवसाय से पूरी तरह से बाहर निकालने के गुप्त उद्देश्य के साथ दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि रद्द करने के आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को पहले से ही उनके कब्जे में मौजूद स्टॉक का निपटान करने में असमर्थ बना दिया गया है, हालांकि साथ ही उनके लाइसेंस को रद्द करने के बाद इस तरह के स्टॉक का रखना कोयला नियंत्रण आदेश के तहत एक अपराध बन गया है।

हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि कोयला 1946 के आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम के तहत एक आवश्यक वस्तु है, और केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रांतीय सरकार को शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार कोयले की आपूर्ति और वितरण को इस तरह से विनियमित करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा प्रावधान करने में सक्षम थी, जिसे वे अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को सुरक्षित करने की दृष्टि से उचित समझते थे। यह आवश्यक है कि ये प्रावधान संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करें और यदि वे व्यापार या व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वे संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में निर्धारित आम जनता के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंध होने चाहिए।

कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि समुदाय के लिए आवश्यक मानी जाने वाली वस्तुओं का समान वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से इन वस्तुओं की बिक्री को विनियमित करना काफी उचित बात है, जिन्हें निर्दिष्ट मात्रा में कोटा आवंटित किया जाता है और जिन्हें उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है। लाइसेंस देने या रोकने या माल की कीमतें तय करने की शक्ति अनिवार्य रूप से कुछ सार्वजनिक अधिकारियों

या निकायों में निहित होनी चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से इन मामलों में कुछ विवेक के साथ छोड़ना होगा। अब तक कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है; लेकिन शरारत तब उत्पन्न होती है जब ऐसे अधिकारियों को प्रदान की गई शक्ति किसी भी नियम या सिद्धांत द्वारा अनियंत्रित एक मनमानी शक्ति होती है और यह पूरी तरह से विशेष व्यक्तियों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे किसी भी उच्च प्राधिकरण द्वारा किसी भी नियंत्रण या नियंत्रण के बिना कुछ भी करना चाहते हैं। एक कानून या व्यवस्था, जो सामान्य रूप से उपलब्ध वस्तुओं में व्यापार या व्यवसाय को विनियमित करने के मामले में कार्यपालिका को मनमाना और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करती है, को अनुचित नहीं माना जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा चिंतामोन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1) में अभिनिर्धारित किया गया है, वाक्यांश "उचित प्रतिबंध" का तात्पर्य है कि किसी अधिकार के उपभोग में किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा मनमाना या अत्यधिक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए जो जनता के हित में आवश्यक है। विधान, जो मनमाने ढंग से या अत्यधिक रूप से अधिकार पर आक्रमण करता है, को तर्कसंगतता की गुणवत्ता को समाहित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, और जब तक कि यह अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित संतुलन नहीं बनाता है, तब तक इसे तर्कसंगतता में अभाव माना जाना चाहिए। यह

इन सिद्धांतों के आलोक में है कि हम इस नियंत्रण आदेश के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी वैधता याचिकाकर्ताओं की ओर से हमारे सामने आक्षेपित की गई है।

आदेश के खंड 3 (1) में निहित प्रावधान कि "कोई भी व्यक्ति इस आदेश के तहत दिए गए लाइसेंस के अलावा कोयले का भंडारण, बिक्री, भंडारण या अन्यथा उपयोग या निपटान नहीं करेगा" एक सामान्य प्रावधान के रूप में काफी असाधारण है; वास्तव में, यह प्राथमिक उद्देश्य है जिसे पूरा करने का नियंत्रण आदेश का इरादा है। इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं: पहला उपखंड (2) (ए) में निर्धारित किया गया है और इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है या नहीं ली जा सकती है। उपखंड (2) (बी) में सन्निहित दूसरे अपवाद पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आपत्ति जताई है। इस अपवाद में यह प्रावधान है कि खंड 3 (1) में कुछ भी राज्य कोयला नियंत्रक द्वारा उपरोक्त उपखंड के किसी भी प्रावधान से छूट प्राप्त किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर ऐसी छूट की सीमा तक लागू नहीं होगा। यह देखा जाएगा कि नियंत्रण आदेश कहीं भी यह इंगित नहीं करता है कि छूट के लिए आधार क्या हैं, और न ही इस बिंदु पर कोई नियम बनाए गए हैं। राज्य नियंत्रक को छूट देने के लिए एक अप्रतिबंधित शक्ति दी गई है, और भले ही वह मनमाने ढंग से या अनुचित उद्देश्यों से कार्य करता है,

इस पर कोई रोक नहीं है और न ही निवारण प्राप्त करने का कोई तरीका है। इसलिए नियंत्रण आदेश का खंड 3 (2) (बी) हमें प्रथम दृष्टया अनुचित लगता है। तथापि, हम श्री उमरीगर के साथ सहमत हैं कि नियंत्रण आदेश का यह भाग, भले ही खराब हो, बाकी हिस्सों से अलग है और हम वास्तव में वर्तमान मामले में इस प्रावधान की वैधता या अन्यथा से चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसके तहत की गई कोई कार्रवाई हमारे समक्ष किसी भी शिकायत का विषय नहीं है।

नियंत्रण आदेश के खंड 4 (3) के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिक दुर्जेय आपत्ति ली गई है जो लाइसेंस देने और अस्वीकार करने से संबंधित है। लाइसेंस प्राधिकरण को इस आदेश के तहत किसी भी लाइसेंस को देने या देने से इनकार करने, नवीनीकरण करने या नवीनीकरण करने, निलंबित करने, रद्द करने या संशोधित करने से इनकार करने की पूर्ण शक्ति दी गई है और उसे केवल अपनी कार्रवाई के कारणों को दर्ज करना है। इतना ही नहीं, शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे राज्य कोयला नियंत्रक इसे सौंपने का विकल्प चुन सकता है, और चुनाव किसी भी और प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रावधान को उचित नहीं माना जा सकता है। लाइसेंस अधिकारी के विवेक को विनियमित या निर्देशित करने के लिए इन मामलों पर कोई नियम नहीं

बनाए गए हैं और न ही कोई निर्देश दिए गए हैं। व्यावहारिक रूप से आदेश किसी एकल व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छा के लिए प्रतिबद्ध है कि वह किसी भी तरह से लाइसेंस प्रदान करने, रोकने या रद्द करने की शक्ति रखता है और आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शक्ति का उचित निष्पादन सुनिश्चित कर सके या अन्याय पर रोक के रूप में काम कर सके जो उसके अनुचित निष्पादन के परिणामस्वरूप हो सकता है। श्री उमरीगर का तर्क है कि सत्ता के किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ इस तथ्य के कारण पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है कि लाइसेंस प्राधिकरण को उनके कार्यों के कारण दर्ज करने हैं। यह सुरक्षा, हमारी राय में, शायद ही प्रभावी है; क्योंकि आदेश में निर्धारित कोई उच्च प्राधिकारी नहीं है जो इन कारणों की औचित्य की जांच कर सके और अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय को संशोधित या समीक्षा कर सके। इसलिए जिन कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है, वे केवल लाइसेंस प्राधिकरण की व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए हैं और पीड़ित व्यक्ति को कोई उपाय प्रदान करने के लिए नहीं हैं। श्री जस्टिस मैथ्यूज ने यीक वो बनाम हॉपकिंस (') के प्रसिद्ध अमेरिकी मामले में यह इंगित किया था और पूर्ण औचित्य के साथ कहा था कि इस तरह के पद पर रखे गए अधिकारियों की कार्रवाई या गैर-कार्रवाई शत्रुता या पूर्वाग्रह से, पक्षपातपूर्ण उत्साह या शत्रुता से, पक्षपात और अन्य अनुचित प्रभावों और उद्देश्यों से हो सकती है जो छिपाने में आसान हैं और जिनका पता

लगाना और उजागर करना मुश्किल है, और परिणामस्वरूप इस तरह की अप्रतिबंधित शक्ति के आवरण में किए जाने में सक्षम अन्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट हो जाता है, बिना विस्तृत जांच की आवश्यकता के। हमारी राय में, उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश के खंड 4 (3) के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने और अनुच्छेद के खंड (6) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के भीतर नहीं आने के रूप में शून्य माना जाना चाहिए।

चूंकि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश की पूरी संरचना का एक अभिन्न अंग है, इसलिए आदेश तब तक ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक कि खंड 4 (3) के प्रावधान को ऊपर दर्शाई गई संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं लाया जाता है। याचिकाकर्ताओं का लाइसेंस नियंत्रण आदेश के उपरोक्त खंड के अनुसरण में रद्द कर दिया गया है, रद्द करना ही अप्रभावी माना जाना चाहिए और हमारे लिए यह जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या वे आधार जिनके आधार पर लाइसेंस प्राधिकरण ने कार्य करने का इरादा किया था वे अस्पष्ट या अनिश्चित थे या रद्द करने के लिए उचित आधार हो सकते हैं।

नियंत्रण आदेश के दो अन्य खंड जिन पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अपवाद लिया गया है, वे खंड (7) और (8) हैं। खंड (7) राज्य

कोयला नियंत्रक को लिखित आदेश द्वारा, कोयले का भंडार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को स्टॉक का पूरा या कोई हिस्सा बेचने का निर्देश देने का अधिकार देता है और ऐसी शर्तों और कीमतों पर जो खंड (8) के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किए जाएं। खंड 8 (1) में प्रावधान है कि फॉर्म 'बी' में कोई भी लाइसेंसधारी अनुसूची III में दिए गए सूत्र के अनुसार लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत से अधिक कीमत पर कोयला नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा। इन दोनों खंडों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क, सार में, यह है कि अनुसूची आईएल में निर्धारित मूल्य निर्धारित करने का सूत्र स्वयं अनुचित है क्योंकि यह लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधिकार के प्रयोग पर निर्भर है। यह तर्क दिया जाता है कि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा मूल्य का अनुचित निर्धारण कोयला व्यापारियों के व्यवसाय के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा और याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 16 जुलाई, 1953 को की गई कीमतों की घोषणा द्वारा ठीक यही किया गया है।

हमने नियंत्रण आदेश की अनुसूची में दिए गए सूत्र की कुछ सावधानी के साथ जांच की है और जो सामग्री वास्तव में हमारे सामने रखी गई है, हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि सूत्र अनुचित है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कीमतों की गणना डिपो तक कोक और कोयले की भूमि लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें 10 प्रतिशत का लाभ जोड़ा जाता है। भूमि की लागत में कुल सात मर्दें शामिल हैं जो अनुसूची III में सूचीबद्ध हैं। अनुसूची की मर्दें 1,2,3,4 और 6 के संबंध में वास्तविक लागतों को ध्यान में रखा जाता है और इस पर संभवतः कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती है। पूरा विवाद मर्द 5 में निर्दिष्ट आनुषंगिक शुल्कों और कमी के लिए भत्ते के संबंध में है जो मर्द 7 बनाता है। जहाँ तक आनुषंगिक शुल्कों का संबंध है, अनुसूची अधिकतम रु। 8-8-0 प्रति टन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना है। दरें निस्संदेह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होती हैं और ऐसे मामलों में कुछ विवेक स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ना होगा। हालाँकि, इन दरों को तय करने में लाइसेंस प्राधिकरण को दिया गया विवेकाधिकार असीमित विवेकाधिकार नहीं है, लेकिन इसका उपयोग उस इलाके में प्रचलित स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय अधिकारियों को परिचित माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि 16 जुलाई, 1953 की घोषणा में, लाइसेंस प्राधिकरण ने केवल एक लाख रुपये की दर से आकस्मिक शुल्क की अनुमति दी थी। 4-12-0 प्रति टन और यह सरासर अनुचित है। यह बताया गया है कि लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर बहुत अधिक दरों की अनुमति दी गई

थी, हालांकि इन स्थानों की स्थानीय स्थितियां लगभग समान हैं। और परिणामस्वरूप इस संबंध में एक भेदभाव हुआ है जो घोषणा को पूरी तरह से अमान्य कर देता है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान किसी भी व्यक्ति के किसी भी हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं हैं जो अन्य स्थानों की स्थानीय स्थितियों से परिचित हैं और जो सामग्री हमें यहां मिली है, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि कानपुर के लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरें वास्तव में भेदभावपूर्ण हैं। यह निश्चित है कि आप लाइसेंस प्राधिकरण के लिए मूल्य निर्धारित करने के मामले में अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार नहीं हैं और बशर्ते कि हम संतुष्ट हों कि एक लोक अधिकारी में निहित विवेकाधिकार एक अनियंत्रित विवेकाधिकार नहीं है और इसके प्रयोग से कोई अनुचित भेदभाव नहीं हुआ है, हम संभवतः ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या घोषणा को अवैध नहीं मान सकते हैं।

यही कारण, हमारी राय में, अनुसूची III की सातवीं मद पर लागू होते हैं जो वजन की कमी के लिए भत्तों से संबंधित है। यहाँ भी नियंत्रण आदेश अधिकतम निर्दिष्ट करता है और विशेष मामलों में भत्ते का निर्धारण लाइसेंस प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हम अपने सामने रखी गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं कि यह प्रावधान अनुचित या भेदभावपूर्ण है। यह सूत्र वस्तु संख्या 5 के अपवाद के साथ लागत

वस्तुओं पर 10 प्रतिशत के लाभ की अनुमति देता है जो आनुषंगिक शुल्कों से संबंधित है. हम नहीं जानते कि इस वस्तु को क्यों हटा दिया गया है और उत्तरदाताओं की ओर से पेश श्री उमरीगर इसके लिए कोई संभावित कारण नहीं बता सके। लेकिन फिर भी, इस चूक का परिणाम लाभ के मार्जिन को केवल 10 प्रतिशत से थोड़ा कम करना होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि इलाके के अन्य व्यापारी उस राशि के लाभ के साथ कोयले का व्यवसाय करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि उत्तरदाताओं के हलफनामे में कहा गया है, तो लाभ का ऐसा निर्धारण निस्संदेह जनता के हित में होगा और इसे अनुचित नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क सही नहीं है कि नियंत्रण आदेश ने केवल अधिकतम लाभ 10 प्रतिशत निर्धारित किया है और इसे किसी भी तरह से कम करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया है। अनुसूची III लाभ को 10 प्रतिशत पर निर्धारित करती है. वस्तु संख्या 5 के अपवाद के साथ भूमि लागत पर और चूंकि यह अधिकतम नहीं है, इसलिए इसे सभी मामलों में अनुमति देनी होगी और खंड 8 (1) के तहत, 'बी' लाइसेंसधारियों को अनुसूची संख्या के तहत निर्धारित कीमतों के अनुसार कोयले के अपने स्टॉक को बेचना होगा। खंड 8 (2) वास्तव में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह कोयला भंडार के सभी धारकों पर भूमि लागत से अधिक मूल्य वसूलने और उस पर 10 प्रतिशत से अधिक लाभ

नहीं वसूलने के लिए अक्षमता लागू करने का प्रावधान करता है जो लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ जिस निर्धारण की बात की गई है, वह अनुसूची III में जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार होना चाहिए और जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह एक निश्चित दर निर्दिष्ट करता है न कि अधिकतम और लाइसेंस प्राधिकरण को अपनी पसंद की कोई कटौती करने की अनुमति नहीं देता है। कुल मिलाकर हमारी राय है कि नियंत्रण आदेश के खंड (7) और (8) याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त व्यापार की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और परिणामस्वरूप 16 जुलाई, 1953 की घोषणा को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। परिणाम यह है कि, हमारी राय में, नियंत्रण आदेश के खंड 4 (3) के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को रद्द करना अमान्य माना जाना चाहिए और प्रत्यर्थियों को रद्द करने के आदेश को लागू करने से रोकने वाले विरोधी पक्षों के खिलाफ अनिवार्य रूप से एक रिट जारी की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की बाकी प्रार्थनाओं की अनुमति नहीं है। हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

याचिका की आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ताओं के लिए अभिकर्ता: गणपत राय।

उत्तरदाताओं के लिए अभिकर्ता: सी पी लाल।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।